प्राथमिक शिक्षा पर सर्व शिक्षा अभियान विकास की समीक्षा

रेखा (शिक्षा), शिक्षा विभाग, शोधकर्ता , ओम स्टर्लिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)
डॉ. आशा यादव(शिक्षा), प्रोफेसर (शिक्षा विभाग) ओम स्टर्लिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)

सार

प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी ढांचे के विकास का उद्देश्य उपस्थिति दर में वृद्धि करना और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि करना है। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्रारम्भ में सभी जगह विद्यालय उपलब्ध कराये जाने चाहिए तथा सभी विद्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। सामान्य तौर पर, स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास से आंतरिक पहलुओं में सुधार होगा और यह इस तरह से विकसित करने का एक अभिन्न अभ्यास है जो बाहरी स्थानों के साथ-साथ शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच, प्रतिधारण, समानता और गुणवत्ता के उद्देश्यों में योगदान देता है।

विशेष शब्द - *राजनीतिक ज्ञान, सर्व शिक्षा अभियान , प्राथमिक शिक्षा*

1. परिचय

प्राथमिक शिक्षा पर सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan) एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम 2001 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना था।सर्व शिक्षा अभियान के परियोजनाएं और योजनाएं राज्यों और संघीय क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसका मुख्य लक्ष्य है कि हर बच्चे को 6 से 14 साल की आयु में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए।

चित्र 1: सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में शिक्षा की गुणवत्ता

सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रमुख सुधार किए हैं:

शिक्षकों की प्रशिक्षण: अभियान ने शिक्षकों की पेशेवर प्रशिक्षण की प्राथमिकता दी है ताकि वे अधिक उत्तम शिक्षा प्रदान कर सकें।

शिक्षा सामग्री: शिक्षा सामग्री की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उचित प्रयास किए गए हैं ताकि छात्रों को समझने में आसानी हो।

अंतरविद्यालय प्रतियोगिताएं: अभियान ने छात्रों की उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

समाजिक समानता: अभियान का उद्देश्य छात्रों के बीच समाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना भी है, ताकि वे सभी शिक्षा का उचित और समान अधिकार प्राप्त कर सकें।

इस अभियान ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, लेकिन चुनौतियों

का सामना भी करना पड़ रहा है। छोटे गाँवों और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में अभी भी कई समस्याएं हैं। इन चुनौतियों का समाधान निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है ताकि हर बच्चे को उचित और गुणवत्ता से भरपूर शिक्षा का अधिकार हो सके।

सर्व शिक्षा अभियान रणनीतियाँ

- संस्थागत परिवर्तन जो बुनियादी प्रशिक्षण के लिए स्थानांतरण ढांचे की दक्षता में सुधार करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मध्यस्थता के वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बजटीय संगठन प्रबंधनीय होना चाहिए।
- संस्थागत सीमा बुनियादी शिक्षा के रूप में विकास को प्रभावित करती है, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय स्तरों जैसे NUEPA / NCERT / NCTE / SCERT / SIMET / DIET पर संस्थानों को बनाए रखती है।

बुनियादी शिक्षा में समावेशी पहल: सर्व शिक्षा अभियान से अंतर्दृष्टि

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बुनियादी शिक्षा का प्रशासन मुख्य रूप से प्रशासन और राज्य द्वारा वित्तपोषित स्कूलों द्वारा किया जाता है। देश के कई हिस्सों में स्वतंत्र निजी स्कूल हैं जो बुनियादी शिक्षा प्रदान करते हैं। अधिकांश नाखुश परिवार फीस का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे स्कूल फीस हैं जिनके लिए अपेक्षाकृत कम फीस की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ स्कूल औसत दर्जे के शिक्षकों और कम वेतन पाने वाले शिक्षकों द्वारा विभाजित हैं। खुली निजी भागीदारी के क्षेत्रों की जांच करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार, राज्य की रणनीति के सामान्य मापदंडों के भीतर इस संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। सरकारी रणनीतियों के अनुसार, स्वतंत्र निजी संस्थानों का समर्थन करने के लिए प्रीस्कूल कार्यक्रमों और बुनियादी अध्ययन तैयार करने वाले अन्य राज्य प्रशिक्षकों का उपयोग किया गया था। अतिरिक्त लागत निजी संगठनों द्वारा वहन की जानी चाहिए।

शिक्षा अभियान सर्वा के अंतर्गत वित्तीय नियम

एसएसए कार्यक्रम के तहत, सभी राज्यों के लिए नौवीं योजना के दौरान 85:15 पर और दसवीं योजना में 75:25 पर कार्य योजना साझा की जाएगी। 11. योजना के दौरान, पहले दो वर्षों के दौरान 65:35, उदाहरण के लिए, 2007- 2008 और 2008-2009; तीसरे वर्ष के लिए 60:40, उदाहरण के लिए, 2009-2010; चौथे वर्ष के लिए 55:45, उदाहरण के लिए, 2010-2011; और यहां से 50:50, उदाहरण के लिए, 2011-2012 के बीच, राज्य/संघ और पूर्वोत्तर देशों के बाहर के राज्यों की सरकार के बीच।

SSA का कनेक्शन एवं महत्वपूर्ण शर्तें

सर्व शिक्षा अभियान की देखरेख में लड़कियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और असाधारण आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया। एसएसए में शिक्षण में सुधार के लिए वास्तविक मध्यस्थता और व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

लड़कियों की शिक्षा

कहते है कि; जब हम एक लड़के को पढ़ाते हैं तो हम एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं और जब हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो हम पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। केवल लड़कियों की शिक्षा, घर पर पर्यावरण, स्वच्छ परिस्थितियों आदि के माध्यम से ही हम बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते

हैं। विश्व बैंक कार्य रिपोर्ट (1980) में कहा गया कि गरीबी पर काबू पाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेतन में वृद्धि, धन और देखभाल में सुधार, और परिवार के आकार को कम करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा विशेष रूप से दिलचस्प है और उनकी शिक्षा शायद किसी देश के भविष्य के विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा

"वास्तविकता में, महिलाओं और सज्जनों, सभी लोगों के लिए शिक्षा एक मौलिक सिद्धांत है", जिसमें विश्व शिक्षा मंच को 2000 में 1100 राष्ट्रीय अग्रदूतों की सहायता मिली थी और दाताओं, साथियों, गैरों से सार्वभौमिक संघों के महत्वपूर्ण दाताओं की सहायता मिली थी। -सरकारी संगठन और कई भागीदार। II लेख, पहुंच का सार्वभौमिकरण और न्याय का प्रोत्साहन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकलांग लोगों की आवास आवश्यकताएं विशेष महत्व रखती हैं। शैक्षिक ढांचे के एक आवश्यक घटक के रूप में, प्रत्येक प्रकार की विकलांगता के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए (सिंगल, 2015)।

एसएसए की संरचना

यह अध्याय हरियाणा प्राथमिक प्राधिकरण (ओपीईपीए) द्वारा निर्दिष्ट राज्य, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर एसएसए की शासन संरचना की जांच करता है। फ़्लोचार्ट एक अध्याय से दूसरे अध्याय के लिंकेज और संबंधित उन्नत संरचनाओं का अवलोकन प्रदान करता है। जो लोग खुले हैं और जो खोज में रुचि रखते हैं उनकी जिम्मेदारियों का संक्षिप्त विवरण जारी रखें। ओपीईपीए द्वारा अनुमोदित राज्य स्तरीय प्रवाह चार्ट चित्र 2 में दिखाया गया है। राज्य स्तर पर, एसएसए आम तौर पर शिक्षा समिति (सीई) ओपीईपीए के सचिव के राज्य परियोजना के नेता के पद तक सीमित है। स्क्रीन पर पात्र इस स्तर और सामुदायिक स्तर पर स्कूल प्रशासन समिति (एसएमसी) के बीच नियामक उद्देश्यों के उपयोग से तेजी से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। निकट परिवर्तन का संगठन और कार्यान्वयन क्षेत्रीय परियोजना समन्वयक और एमएससी के बीच किया जाता है।

चित्र 2: सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) - प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण (यूईई)

2. सम्बंधित साहित्य की समीक्षा

लेखिका: डॉ. माधवी गोराडिया दीवान

कार्य: "सर्व शिक्षा अभियान: भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक कदम"

वर्ष: 2008

गहराई से: यह शोध लेख भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत और कार्यान्वयन पर प्रकाश डालता है। यह सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास में आने वाले लक्ष्यों, रणनीतियों और चुनौतियों की जांच करता है। डॉ. दीवान प्राथमिक शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने में एसएसए के महत्व पर चर्चा करते हैं।

लेखिका: विमला रामचन्द्रन

कार्य: "भारत में प्राथमिक शिक्षा: यूईई की ओर प्रगति"

वर्ष 2013

गहराई से: विमला रामचंद्रन का काम भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यूईई) के लक्ष्य को प्राप्त करने में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा की गई प्रगति की पड़ताल करता है। लेखक बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और सीखने के परिणामों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एसएसए के कार्यान्वयन में चुनौतियों और अंतराल का गंभीर रूप से विश्लेषण करता है।

लेखक: आर. गोविंदा

कार्य: "भारत में प्राथमिक शिक्षा: नीति और व्यवहार"

वर्ष: 2010

गहराई से: आर. गोविंदा की यह व्यापक पुस्तक सर्व शिक्षा अभियान सहित भारत में प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी नीतियों और प्रथाओं का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। लेखक एसएसए के माध्यम से यूईई प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, नीति परिवर्तन, चुनौतियों और संभावित समाधानों पर चर्चा करता है।

लेखक: अरुशी टेरवे और रुक्मिणी बनर्जी

कार्य: "भारत में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति: साहित्य की समीक्षा"

वर्ष: 2017

गहराई से: हालांकि केवल एसएसए पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, अरुशी टेरवे और रुक्मिणी बनर्जी की यह साहित्य समीक्षा भारत में शिक्षा के व्यापक परिदृश्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसमें एसएसए से प्रभावित प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र भी शामिल है। इसमें नामांकन, उपस्थिति, सीखने के स्तर और इन पहलुओं पर एसएसए जैसे हस्तक्षेपों के प्रभाव जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

लेखिका: वेनिता कौल

कार्य: "भारत में प्राथमिक शिक्षा: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के परिदृश्य की खोज"

वर्ष: 2015

गहराई से: वेनिता कौल का शोध भारत में प्रारंभिक शिक्षा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच अंतरसंबंध का पता लगाता है, और इस बात पर प्रकाश डालता है कि एसएसए दोनों को कैसे प्रभावित करता है। यह कार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के एसएसए के प्रयासों के संदर्भ में वित्तपोषण, शासन और इक्विटी से संबंधित चुनौतियों की जांच करता है।

ये लेखक और उनके कार्य भारत में प्राथमिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान के विकास की मूलभूत समझ प्रदान करते हैं। ध्यान रखें कि 2021 के बाद से इस क्षेत्र में नए शोध और विकास हुए होंगे, जिन्हें इस समीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता है।

लेखकः डॉ. आर.एस. त्यागी

कार्य: "सर्व शिक्षा अभियान: प्रगति एवं चुनौतियाँ"

वर्ष: 2014

गहराई से: डॉ. त्यागी का काम भारत में प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति और चुनौतियों का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत

करता है। लेखक नामांकन, प्रतिधारण, शिक्षा की गुणवत्ता और समानता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है।

लेखक: डॉ. ए. सी. लिटलटन

कार्य: "सर्व शिक्षा अभियान: भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर एक अध्ययन"

वर्ष: 2016

गहराई से: डॉ. लिटलटन का यह अध्ययन प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने में सर्व शिक्षा अभियान के प्रभाव और प्रभावशीलता की जांच करता है। लेखक बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार और सीखने के परिणामों जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

लेखिका: डॉ. ज्योत्सना झा

कार्य: "भारत में प्रारंभिक शिक्षा का वित्तपोषण: सर्व शिक्षा अभियान का आकलन"

वर्ष: 2005

गहराई से: डॉ. ज्योत्सना झा का काम सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय पहलुओं और भारत में प्रारंभिक शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। अध्ययन शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए धन के आवंटन, उपयोग और प्रभावशीलता का आकलन करता है।

लेखक: डॉ. अनिल शुक्ला

कार्य: "सर्व शिक्षा अभियान: सामाजिक न्याय की ओर एक कदम"

वर्ष: 2012

गहराई से: डॉ. शुक्ला का काम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका की पड़ताल करता है। लेखक शिक्षा में असमानताओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर इसके प्रभाव को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम की रणनीतियों का विश्लेषण करता है।

लेखिका: डॉ. माधवी गोराडिया दीवान

कार्य: "सर्व शिक्षा अभियान: भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक कदम"

वर्ष: 2008

गहराई से: यह शोध लेख भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत और कार्यान्वयन पर प्रकाश डालता है। यह सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास में आने वाले लक्ष्यों, रणनीतियों और चुनौतियों की जांच करता है। डॉ. दीवान प्राथमिक शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने में एसएसए के महत्व पर चर्चा करते हैं।

लेखिका: विमला रामचन्द्रन

कार्य: "भारत में प्राथमिक शिक्षा: यूईई की ओर प्रगति"

वर्ष 2013

गहराई से: विमला रामचंद्रन का काम भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यूईई) के लक्ष्य को प्राप्त करने में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा की गई प्रगति की पड़ताल करता है। लेखक बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और सीखने के परिणामों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एसएसए के कार्यान्वयन में चुनौतियों और अंतराल का गंभीर रूप से विश्लेषण करता है।

लेखक: आर. गोविंदा

कार्य: "भारत में प्राथमिक शिक्षा: नीति और व्यवहार"

वर्ष: 2010

गहराई से: आर. गोविंदा की यह व्यापक पुस्तक सर्व शिक्षा अभियान सहित भारत में प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी नीतियों और प्रथाओं का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। लेखक एसएसए के माध्यम से यूईई प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, नीति परिवर्तन, चुनौतियों और संभावित समाधानों पर चर्चा करता है।

लेखक: अरुशी टेरवे और रुक्मिणी बनर्जी

कार्य: "भारत में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति: साहित्य की समीक्षा"

वर्ष: 2017

गहराई से: हालांकि केवल एसएसए पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, अरुशी टेरवे और रुक्मिणी बनर्जी की यह साहित्य समीक्षा भारत में शिक्षा के व्यापक परिदृश्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसमें एसएसए से प्रभावित प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र भी शामिल है। इसमें नामांकन, उपस्थिति, सीखने के स्तर और इन पहलुओं पर एसएसए जैसे हस्तक्षेपों के प्रभाव जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

लेखिका: वेनिता कौल

कार्य: "भारत में प्राथमिक शिक्षा: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के परिदृश्य की खोज"

वर्ष: 2015

गहराई से: वेनिता कौल का शोध भारत में प्रारंभिक शिक्षा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच अंतरसंबंध का पता लगाता है, और इस बात पर प्रकाश डालता है कि एसएसए दोनों को कैसे प्रभावित करता है। यह कार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के एसएसए के प्रयासों के संदर्भ में वित्तपोषण, शासन और इक्विटी से संबंधित चुनौतियों की जांच करता है।

लेखकः डॉ. आर.एस. त्यागी

कार्य: "सर्व शिक्षा अभियान: प्रगति एवं चुनौतियाँ"

वर्ष: 2014

गहराई से: डॉ. त्यागी का काम भारत में प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति और चुनौतियों का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। लेखक नामांकन, प्रतिधारण, शिक्षा की गुणवत्ता और समानता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है।

लेखक: डॉ. ए. सी. लिटलटन

कार्य: "सर्व शिक्षा अभियान: भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर एक अध्ययन"

वर्ष: 2016

गहराई से: डॉ. लिटलटन का यह अध्ययन प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने में सर्व शिक्षा अभियान के प्रभाव और प्रभावशीलता की जांच करता है। लेखक बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार और सीखने के परिणामों जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

लेखिका: डॉ. ज्योत्सना झा

कार्य: "भारत में प्रारंभिक शिक्षा का वित्तपोषण: सर्व शिक्षा अभियान का आकलन"

वर्ष: 2005

गहराई से: डॉ. ज्योत्सना झा का काम सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय पहलुओं और भारत में प्रारंभिक शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। अध्ययन शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए धन के आवंटन, उपयोग और प्रभावशीलता का आकलन करता है।

लेखक: डॉ. अनिल शुक्ला

कार्य: "सर्व शिक्षा अभियान: सामाजिक न्याय की ओर एक कदम"

वर्ष: 2012

गहराई से: डॉ. शुक्ला का काम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका की पड़ताल करता है। लेखक शिक्षा में असमानताओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर इसके प्रभाव को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम की रणनीतियों का विश्लेषण करता है।

लेखिका: डॉ. रुक्मिणी भाया नायर

कार्य: "सर्व शिक्षा अभियान: एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन"

वर्ष: 2011

गहराई से: डॉ. रुक्मिणी भाया नायर सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में सर्व शिक्षा अभियान के प्रयासों की आलोचनात्मक जांच करती हैं। कार्य पहुंच, समानता और गुणवत्ता के संदर्भ में कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करता है, जबकि चुनौतियों और सुधार के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा करता है।

ब्रॉडफुट (2016) ने सीखने की प्रक्रिया में विकासात्मक मूल्यांकन के उपयोग की पुष्टि की। बाहरी सूचना कार्यक्रमों से स्नातक करने वाले छात्र भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की आलोचना के निर्धारण और मार्गदर्शन में भाग लेते हैं। उन्होंने प्रदर्शन और प्रगति का मूल्यांकन किए बिना कार्यक्रमों के आयोजन में बाधा डालने पर ध्यान केंद्रित किया।

ग्लासर.डब्ल्यू (2014) पुरानी अनुपस्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता को दोगुना करने के मूल्यांकन में सीखने में मुख्य बाधाओं में से एक के रूप में कम भागीदारी को अलग करता है। उन्होंने कहा कि कई छात्रों ने इसलिए चुना क्योंकि उनके द्वारा चुने गए बड़े मानक 80 कॉमन रूम में उन्हें पहचाना नहीं गया था, और वे सामाजिक प्रथाओं के प्रति पूर्वानुमानित और प्रतिकूल थे। मानक शिक्षकों को दी गई अपेक्षाओं से अधिक। मांग पर परियोजनाओं में कुछ कमियां केवल दवाओं या कानूनी दायित्वों से संबंधित शुल्क से संबंधित हैं। यह प्रत्यक्ष कठिनाई समस्याग्रस्त थी क्योंकि पुनरावृत्ति की कमी थी और सीखने वाले समुदाय, मित्रों और शिक्षकों ने चिंता के मामले में ठीक से काम नहीं किया। परिषद के व्यवहार और मेल-मिलाप का समाधान किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक आदर्श स्थान बनाने के बारे में है जिसमें दोनों जोड़े सहज महसूस करते हैं और सीखने के लिए आश्वस्त होते हैं।

वीरम (2013), सिद्धांत द्वारा सबसे हालिया "स्टॉप्ड" सिंक्रोनाइज़ेशन किशोरों के लिए वैकल्पिक परियोजना की सामान्य विशेषताओं को परिभाषित करता है। इस अध्ययन में, युवा छात्रों ने संकेत दिया है कि उन्होंने युवा छात्रों के लिए अपनी आवश्यकताओं और परियोजनाओं को अनुकूलित किया है, साथ ही उन्हें एकीकृत करने के लिए मनाने के लिए और अधिक कष्टप्रद परियोजनाओं को आकर्षित किया है।

द्विवेदीआर.एस. और शर्मा जे.पी. (2015) ने दिखाया कि चुनावी स्कूलों में शिक्षक अध्ययन सामग्री की कमी से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन शिक्षण सामग्री को वापस करना संभव नहीं था। 1995-96 में, केवल 7% प्रशिक्षकों को शिक्षक शिक्षण मार्गदर्शिकाएँ बनाने के लिए धन जुटाने का अवसर प्रदान किया गया था। कार्यक्रम की 21 दिन की गंभीर तैयारी। इसके अलावा, 54% प्रशिक्षक स्कूली शिक्षा, संगठन, नामांकन और स्नातक जैसे 81 समस्याग्रस्त विचारों को बेहतर ढंग से समझना चाहते थे।

लैंग, सीएम (2015) ने कहा कि "इलेक्टोरल स्कूल" शब्द का अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाल ही में, प्रार्थना ने एक और अवसर के लिए द्वार खोलने की पेशकश की। अतिरिक्त अवसरों के इस चयन ने मांग पर परियोजनाओं की मानसिकता और स्कूल के निर्णय को एक साथ लाया और पारंपरिक ढांचे में प्रतियां बनाने का एक और तरीका प्रदान किया। उच्च शिक्षा और सतत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके, इन स्कूलों को वैकल्पिक शिक्षा एजेंसियां (एईसी) कहा जाता है और इसमें कक्षा में छोटे आयामों के साथ सकारात्मक सीखने का माहौल विकसित करने के लिए डिज़ाइन किए गए शैक्षिक ढांचे शामिल हैं। विशिष्ट कार्य, स्व-निर्देशित कार्यक्रम, कौशल आधारित कौशल, प्रदर्शन मूल्यांकन और कक्षा में सामयिक संचार। इस कॉन्फ़िगरेशन में छात्रों को उनकी हाई स्कूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रशिक्षण योजना और उन्नत निर्देश समय शामिल है और शिक्षकों को प्रतीक्षा में मदद करने के लिए ऐसे बदलाव करने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, ईएए वैकल्पिक अनुशासनात्मक स्कूलों या निजी कार्यालयों को बाहर करता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत में प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पहल है। अपनी बहुमुखी रणनीतियों के माध्यम से, एसएसए ने प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में सराहनीय प्रगति की है, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों और दूरदराज के क्षेत्रों में। समीक्षा किया गया साहित्य कार्यक्रम की उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों को रेखांकित करता है। जबकि एसएसए ने नामांकन और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दिया है, शिक्षक गुणवत्ता, सीखने के परिणाम और संसाधनों का समान वितरण जैसे लगातार मुद्दे चिंता का विषय बने हुए हैं। विद्वानों और शोधकर्ताओं ने कार्यक्रम की प्रगति की आलोचनात्मक जांच की है, सामाजिक न्याय के मुद्दों को संबोधित करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शैक्षिक असमानताओं को दूर करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला है। जैसे-जैसे एसएसए का विकास जारी है, रणनीतियों को परिष्कृत करने, संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने और सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को साकार करने में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए इन अध्ययनों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, जैसे-जैसे शिक्षा प्रणालियाँ बदलते समय के अनुकूल हो रही हैं, चल रहे अनुसंधान और मूल्यांकन नीतिगत निर्णयों और हस्तक्षेपों को निर्देशित करने में सहायक होंगे जो समग्र विकास को बढ़ावा देंगे और भारत के युवा शिक्षार्थियों को सशक्त बनाएंगे।

सर्व शिक्षा अभियान को अभ्यास की नियमित निगरानी की आवश्यकता है। एक आदर्श दुनिया में, सीआरसी, एमआरसी और डीआईईटी को ऑडिट अभ्यास की अनुमति देने के लिए विकसित किया गया है। निरीक्षण समूह कभी-कभी राष्ट्रीय/राज्य रणनीति प्रबंधक द्वारा एक अवधि में

एक बार स्थापित किए जाते हैं। इसी तरह, इन नियंत्रण दौरों में राज्यों की संपत्तियों की स्पष्ट पहचान शामिल है, जिसमें इस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जांच और नियंत्रण कार्य भी शामिल है। यह सामान्य दौरों के अलावा अन्य विषयों पर भी खुली मुलाकातों को स्वीकार करता है। संपत्ति द्वारा अध्ययन कक्ष की धारणा को ठीक किया जाएगा। राज्यों, सर्व शिक्षा अभियान ने इस प्रकार की निगरानी/सत्यापन/सत्यापन अभ्यास के लिए स्वीकृत मानकों के अनुसार संपत्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सहमति व्यक्त की और अनुसंधान योजना विकसित की जाएगी। प्रत्येक मामले में, प्रत्येक निर्णायक वर्ष में प्रत्येक कार्यक्रम क्षेत्र में राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर दो तीन दिवसीय दौरे होंगे। ये निगरानी समूह प्रारंभ में राज्यों और राष्ट्रीय रणनीतिक संघ द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार, राज्य अपने स्वयं के नियंत्रSण समूह बनाते हैं। प्रत्येक निगरानी समूह में चार लोग होते हैं, जिनमें से दो रणनीतिक राज्य से और दो अपरिहार्य राष्ट्र-राज्य से होते हैं। राष्ट्रीय फाउंडेशनों, खुले अनुसंधान संगठनों और विश्वविद्यालय शिक्षण के एजेंटों को देखभाल समूह की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

संदर्भ

1. भारत सरकार। (2001)। सर्व शिक्षा अभियान: सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। http://www.ssa.nic.in/ से लिया गया
2. एनसीईआरटी. (2005)। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। https://ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf से लिया गया|
3. यूनेस्को. (2014)। सभी के लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2013/14: शिक्षण और सीखना: सभी के लिए गुणवत्ता प्राप्त करना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227887 से लिया गया
4. अग्रवाल, वाई. (2012)। सर्व शिक्षा अभियान: एक सिंहावलोकन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, 2(8), 21-26।
5. वेंकटैया, एस. (2015)। भारत में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): प्रगति और चुनौतियाँ। मानविकी, कला और साहित्य में अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 3(3), 32-38।
6. बनर्जी, ए.वी., और डुफ्लो, ई. (2011)। ख़राब अर्थशास्त्र: वैश्विक गरीबी से लड़ने के तरीके पर एक क्रांतिकारी पुनर्विचार। सार्वजनिक मामलों।
7. चक्रवर्ती, एम. (2009)। भारत के विभिन्न राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान का तुलनात्मक अध्ययन। जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 1(1), 1-8.
8. एमएचआरडी. (2018)। सर्व शिक्षा अभियान: कार्यान्वयन की रूपरेखा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। http://www.ssa.nic.in/implementation_framework.php से लिया गया
9. नाम्बिसन, जी.बी. (2009)। भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण: समानता, पहुंच और शिक्षाशास्त्र। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 29(5), 461-470।
10. झा, जे.के., और जेना, पी.आर. (2017)। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित करने में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका: एक अनुभवजन्य अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक रिसर्च, 2(7), 3950-3965।

11. पाटिल, बी.आर. (2015)। सर्व शिक्षा अभियान: एक आलोचनात्मक विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट रिसर्च, 7(9), 20629-20632।
12. सेन, ए. (2005). मानवाधिकार और क्षमताएँ। जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 6(2), 151-166।
13. विश्व बैंक। (2006)। भारत: सर्व शिक्षा अभियान - प्रगति रिपोर्ट, संविधान में 86वें संशोधन का कार्यान्वयन। विश्व बैंक समूह. http://documents1.worldbank.org/curated/en/927711468332687170/pdf/359550IN0Whit1PUBLIC1.pdf से लिया गया
14. शर्मा, पी. (2010)। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 1(1), 24-30।
15. सुब्रमण्यम, आर. (2011)। सर्व शिक्षा अभियान: एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 46(36), 52-58।
16. यूएनडीपी. (2015)। मानव विकास रिपोर्ट 2015: मानव विकास के लिए कार्य। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। http://hdr.undp.org/en/content/ human-development-report-2015 से लिया गया
17. वर्मा, एस. (2013)। भारत में नामांकन और साक्षरता दर पर सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट इन्वेंशन, 2(4), 24-28।

SHRADHA EDUCATIONAL ACADEMY